Vol 3 Issue 9 March 2014

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 ISSN No.2231-5063

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest,Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.net

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Volume-3 | Issue-9 | March-2014
Available online at www.aygrt.isrj.net

GRT

''पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि : एक परिदृष्य''

संगीता मेश्राम

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शास.एस.एस.पी. महाविद्यालय, वारासिवनी तहसील वारासिवनी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

सारांश :-भारतीय संविधान में महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त हैं। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा सत्ता के विकेन्द्रीकरण में महिलाओं को अनिवार्य सहभागिता भी प्रदान की गई हैं। सहभागीता केवल औपचारिक नहीं अपितु सक्रीय होनी चाहिये। ग्रामीण महिला पंचायत प्रतिनिधि भी निरंतर समस्याओं से जुझते हुये अपनी भूमिका के कुशल निर्वहन में सतत् प्रयासरत हैं। उनकी राह अभी भी कठीन हैं किंतु पंचायती राज संस्था के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं नें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया हैं। ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता धीरे–धीरे बढ़ रहीं हैं।

सीमायें :

प्रस्तुत शोध पत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिला पंचायत जनप्रतिनिधियों की स्थिति उनकी समस्याओं एवं निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला गया हैं।

प्रस्तावना :

विश्व भर में महिलाओं को पुरूषों के समक्ष समानता के स्तर पर लाने के प्रयास हो रहे हैं। भारत देश ने भी एक लोकतांत्रिक एवं समानता के पक्षधर की भूमिका में महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं अवसरों की प्राप्ति की स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत देश की बहुसंख्यक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया हैं एवं 73 वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित कर दी गयी हैं। राजनीति में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में भारतीय समाज की दृष्टि प्रारंभ से ही संकीर्ण और अनुदार रही हैं, ऐसे में ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।

पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ हैं। उत्तरदायित्वों एवं बाधाओं के मध्य संघर्षरत महिला पंचायत प्रतिनिधि घर और बाहर ग्रामीण विकास के कार्यो को पूर्ण करने में सतत् प्रयासरत हैं। आज 73 वें संविधान संशोधन के लगभग 20 वर्ष पश्चात् भी ग्रामीण महिला पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष समस्यायें कम नहीं हुई हैं।

भारत में पंचायती राज एवं महिला आरक्षण :

भारत में पंचायती राज का प्राचीन इतिहास हैं, वैदिक काल में पंचायतों का अस्तित्व था। जातक, रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पंचायतों का विवरण मिलता हैं। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटीश राज में भी पंचायती राज व्यवस्था का कई राज्यों में अनुसरण किया गया किंतु यह जमींदारी एवं सामंतवादी प्रवृत्ति के कारण फल–फूल नहीं पाया। प्राचीन काल में पारस्परिक विवादों का निर्णय पंचायतों द्वारा किया जाता था लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान पंचायते समाप्त होती चली गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सर्वप्रथम 12 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधान मंडल ने पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया और 2 अक्टुबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की नींव रखी गयी।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज के स्वरूप के विकास में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत व्यवस्था को स्वीकार किया गया।

24 अप्रेल 1993 से लागू 73 वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की इसमें संविधान के भाग 8 के बाद ''भाग 9'' जोड़ा गया एवं अनुच्छेद 243 'घ' के अनुसार महिलाओं के लिये पंचायतों में स्थानों के आरक्षण द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सत्ता

के विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में अनिवार्य सहभागिता के द्वार खोल दिये।

समस्यायें :

ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण की दिशा में इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं, ग्रामीण महिलायें संवैधानिक व्यवस्था द्वारा सत्ता में भागीदार बनी हैं, किंतु ग्रामीण परिवेश में उन्हें पंचायती राज के कार्यो को करने में कुछ समस्याओं का सामना अभी भी करना पड़ रहा हैं।

शिक्षा की कमी एवं जानकारियों का अभाव, कमजोर आर्थिक स्थिति, जिविकोपार्जन के कार्यो एवं घर के कार्यो में व्यस्तता के बीच पंचायत के कार्यो को करने में समय की कमी। जातिप्रथा, पर्दाप्रथा, रूढ़ीवादी सामाजिक परिवेश, पुरूष प्रधान सामाजिक मानसिकता एवं परिवार के पुरूष सदस्यों के स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति, कहीं–कहीं पर उत्पीड़न की घटनायें आदि समस्यायें पंचायत के कार्यो को करने में प्रमुख बाधायें हैं।

निवारण के उपाय :

अधिक सुक्ष्म प्रशिक्षण, अनिवार्य शिक्षा अथवा पद पर आने के पश्चात् समय सीमा में शिक्षित करना, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पूर्ण साक्षर किया जाना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना होगा। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कठोर संवैधानिक प्रावधान किये जाने चाहिए। पुरूष मानसिकता में बदलाव हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, जातिप्रथा को दूर करने हेतु सामाजिक समरसता कार्यक्रम आदि उपाय हैं, ये उपाय शासन, समाज, गैर सरकारी संगठन एवं स्वयंसेवी संगठनों आदि के माध्यम से संभव हैं। साथ ही महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उनका आत्म विश्वास बढ़ाना होगा।

निष्कर्ष :

महिला आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं किन्तु महिलाओं की सक्रीय भागीदारी ही उनकी समस्याओं के समाधान में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं फिर भी जिम्मेदारी एवं बाधाओं के मध्य ग्रामीण महिला सत्ता के विकेन्द्रीकरण में एक सशक्त भूमिका की ओर निरंतर अग्रसर हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण महिलाओं को विकास प्रक्रियाओं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता दी हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक, न्याय तथा समानता की अभिव्यक्ति है तथा लोकतांत्रिक जड़ों को सुदृढ़ कर रही हैं।

संदर्भ सूची :

1. पाण्डेय डॉ. जयनारायण, (2007) ''भारत का संविधान'' सेन्ट्रल लॉ एजेंसी इलाहबाद पेज नं. 546, 547.
2. डॉ. पूरनमल, (2009) ''नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व'', पोइन्टर पब्लिशर्स , जयपुर राजस्थान, पृ.क्र. 3, 4, 5, 22, 179.
3. शर्मा, डॉ. के.के., (2009) ''भारत में पंचायती राज'', कालेज बुक डिपो, जयपुर (राजस्थान) पृ.क्र. 33, 34, 36, 37.
4. सिंह, सीमा, (2010) ''पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण'' विद्या विहार नई दिल्ली पृ.क्र. 150.
5. मैथ्यू, जार्ज, (2003) ''भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव'', वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृ.क्र. 43, 132, 133, 138, 139, 140, 270, 272, 281, 282.
6. अग्रवाल, प्रमोद कुमार, (2011) '' भारत में पंचायती राज'' ज्ञान गंगा दिल्ली पृ.क्र. 15, 19, 23.
7. मालवीय सुनिता, (2006) :''भारत में महिला सशक्तिकरण'' म.प्र. में महिला आरक्षण के संदर्भ में, शोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 251, 252, 253.
8. चौहान निशा, (1999–2000) ''ग्रामीण समाज में शिक्षित महिलाओं की स्थिति एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'', लघुशोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 124, 163.
9. सिंह बामेश्वर, (2001) ''भारत में स्थानीय प्रशासन'' राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली, पेज नं. 60, 64.
10. गुजनेर प्रीति, (1999) ''मध्यप्रदेश में पंचायती राज'' (एक समीक्षात्मक अध्ययन) लघुशोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 71, 72, 80, 82.
11. तिवारी परशुराम, (2002) ''पंचायती राज विकास कार्यो में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी'' (इंदौर जिले का एक अध्ययन) शोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 112, 114.
12. मेहता सी.एम., (2003) '' उज्जैन संभाग में नवीन पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'' शोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 169, 170, 171.
13. पंड्या रश्मि, (2007) '' पंचायती राज व्यवस्था के महिला सरपंचों की भूमिका'' (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) शोध प्रबंध, दे.अ.वि.वि. इंदौर पेज नं. 191, 192, 193, 195, 196, 200, 202, 203, 204.
14. सोनी विविन्द्र कुमार, (1999) '' पंचायत के नेतृत्व में आयु एवं लिंगभेद एक अध्ययन'' (इंदौर के महू विकासखंड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में) शोध प्रबंध, डॉ. बा.सा.अं.रा.सा.वि.सं. महू पेज नं. 259, 260, 261.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.net